आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 20.03.2023 से 25.03.2023)

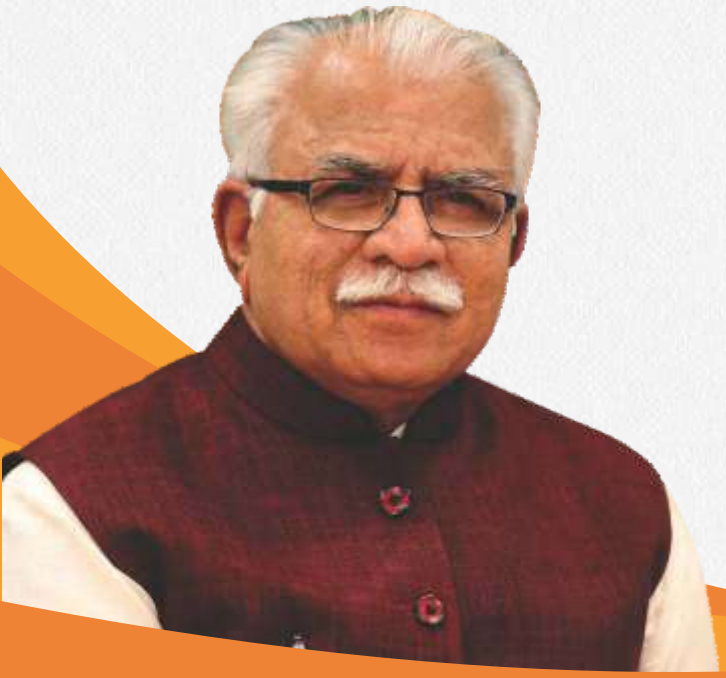

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

विधानसभा सत्र

(दिनांक 20.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक अभय सिंह चौटाला के असंसदीय व्यवहार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अध्यक्ष का सम्मान करना हर सदस्य का परम कर्तव्य है। माननीय अध्यक्ष से किसी भी प्रकार से बहस करना सदन की गरिमा के विरूद्ध है। सदन में प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखने का समान अधिकार है। हालांकि, अध्यक्ष के साथ बहस या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार निश्चित रूप से किसी भी सदस्य से अपेक्षित नहीं है और इस प्रकार के व्यवहार के लिए सख्त संज्ञान लिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलों के हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी की घोषणा भी की।

किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी

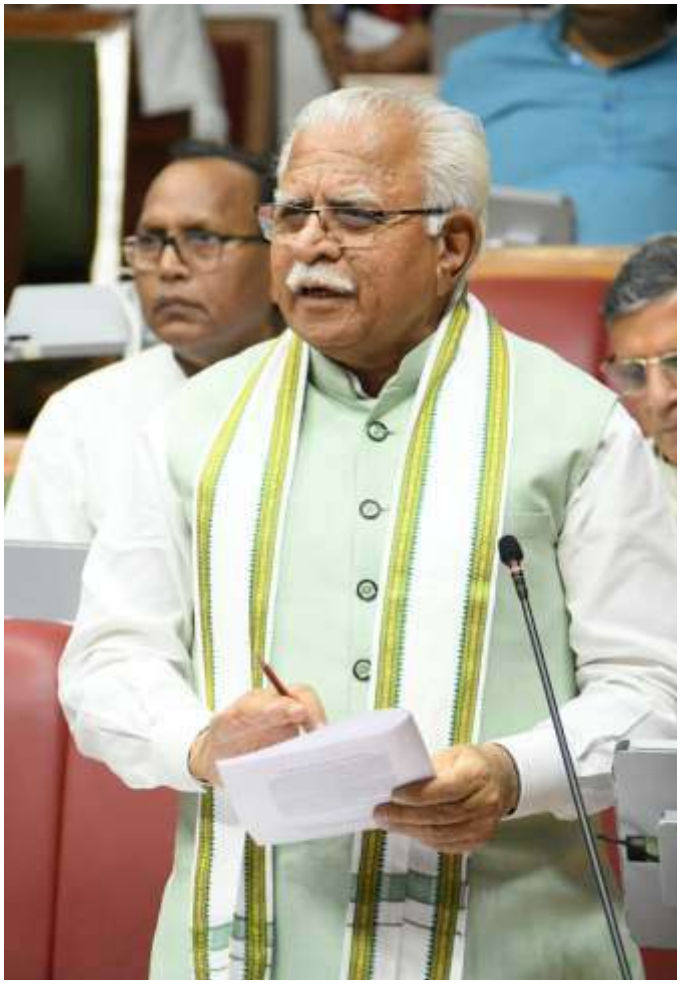

फसल के नुकसान की जानकारी ई–फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर तय समय यानी 72 घंटे में दर्ज करना सुनिश्चित करें ताकि खराब हुई फसलों का समय पर मुआवजा उन्हें दिया जा सके। हरियाणा सरकार अपने किसान

साप्ताहिक सूचना पत्र

भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसानों के हितों की रक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए किसान भाई भी पोर्टल पर अपनी फसल क्षति की जानकारी जल्द से जल्द अपलोड करें ताकि उचित सत्यापन के बाद उन्हें मुआवजे का भुगतान किया जा सके।

विधायक आदर्श ग्राम योजना के संबंध में घोषणा'

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत अब विधायक 2 करोड़ रुपये की राशि गांवों के साथ–साथ शहरों में भी खर्च कर सकेंगे। अब इस योजना को भी विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना कहा जाएगा।

इस योजना के तहत विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक नोडल अधिकारी होंगे। यदि कोई अधिकारी यूसी समय पर नहीं देता तो उसके

खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हुए कहा कि हिसार जिला के गांव बालसमंद में बनने वाले कन्या महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के नाम पर रखा जाएगा। सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सरकार पर कर्ज से संबंधित दिए गए आंकड़ों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 22 नवंबर, 2022 से लेकर अब तक 5 बार उन्होंने अलग–अलग कर्ज के आंकड़े दिए हैं। इस प्रकार के गलत आंकड़े देना नेता प्रतिपक्ष की ही छवि को ही धूमिल करता है। हम विपक्ष की आलोचनाओं से नहीं डरते हैं, बल्कि हमारे व्यवस्था परिवर्तन के काम लगातार जारी रहेंगे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में स्पष्ट करते हुए कहा कि पब्लिक डेब्ट यानी कर्ज के अंदर तीन मद शामिल होते हैं। विपक्ष इन सभी मदों को एक साथ

मिलाकर कर्ज के आंकड़े बताता है, जोकि सही नहीं है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014–15 में स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेज के तहत कर्ज 69,922 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2021–22 में 47,211 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार वर्तमान में कर्ज घटा है।

हमारी जीएसडीपी लगातार बढ़ रही है और वर्तमान में यह लभगग 10 लाख करोड़ तक हो गई है। कर्ज की सीमा जीएसडीपी के 25 प्रतिशत थी, जो कोविड के दौरान 33 प्रतिशत कर दी गई थी। हम आज भी 26–27 प्रतिशत के अंदर है। जबकि पंजाब आज 48 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर 14,334 करोड़ रुपये का कर्ज चला आ रहा था, जिसे हमने 6000 करोड़ रुपये कम करके 8,434 करोड़ रुपये पर लेकर आए हैं। इसी प्रकार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम पर 13,881 करोड़ रुपये का कर्ज था, इसमें भी हमने लगभग 7 हजार करोड़ रुपये कम करके 6,944 करोड़ रुपये पर लेकर आए हैं।

इसी प्रकार वर्ष 2014–15 बिजली निगमों पर लगभग 37 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर्ज था, जो अब घटकर 14,800 करोड़ रुपये रह गया है।

हमारे कार्यकाल में प्रदेश में निवेश की रफ्तार बढ़ी है। जनसंख्या के आधार पर हरियाणा निवेश के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर प्रति व्यक्ति निवेश यानी 303 रुपये के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर, 108 रुपये के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर तथा हरियाणा में 90 रुपये है। उन्होंने कहा कि

साप्ताहिक सूचना पत्र

कृषि क्षेत्र में वर्ष 2023–24 में 7341 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जोकि कुल बजट का 3.9 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमानों में 5758 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2021–22 में 4100 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था।

वर्ष 2014–15 में 2156 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था, जोकि कुल बजट का 3.4 प्रतिशत था।

राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों को स्वायत्त करने की ओर अग्रसर है। वे अपना बजट खुद बनायेंगे और स्वयं खर्च करेंगे। केंद्र व राज्य वित्त आयोग से मिलने वाले पैसे मिलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लोकल ऑडिट सिस्टम को प्रभावी बना रही है। जनता का जो भी पैसा विकास कार्यों पर खर्च होगा, उन सभी का ऑडिट किया जाएगा।

बेरोजगारी से संबंधित

प्रश्न काल के दौरान प्रदेश में बेरोजगारी से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर पहले से घटी है। वर्तमान में फरवरी

साप्ताहिक सूचना पत्र

2023 में रोजगार कार्यालय में दर्ज आवेदकों की संख्या 6.46 लाख है, जबकि दिसंबर 2014 में यह संख्या 7. 86 लाख थी। प्रदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। सरकारी नौकरियों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गए हैं।

वर्ष 2005– 2014 तक 10 वर्षों में 86 हजार सरकारी नौकरियों दी गई। जबकि हमने 8 सालों में 1 लाख 1 हजार से अधिक नौकरियां दी। इसके अलावा, सक्षम युवा योजना के तहत भी स्नातकोत्तर, स्नातक तथा बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 100 घंटे काम के बदले क्रमशः 3000 रुपये, 1500 रुपये तथा 900 रुपये मासिक दिये जाते हैं। अब तक इस योजना में 1.75 लाख युवाओं ने लाभ उठाया है। इतना ही नहीं, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं का कौशल विकास करके भी उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गए हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी 2015

के बाद 12.64 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

टयूबवेल कनेक्शनों के संबंध में

प्रदेश में पानी की कमी और उपलब्ध

पानी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को टयूबवेल कनेक्शन प्राथमिकता आधार पर देगी। सभी को ओपन टयूबवेल कनेक्शन देना संभव नहीं, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में पानी ज्यादा नीचे चला गया है। वर्ष 2018 में आवेदन किए हुए टयूबवेल कनेक्शनों में से 4412 कनेक्शन बकाया है, इन कनेक्शनों को तुरंत दिया जाएगा। वर्ष 2023–24 में इन कनेक्शनों से अगले कनेक्शनों को देने के लिए डिमांड नोट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी ज्यादा नीचे चला गया है, वहां ट्यूबवेल कनेक्शन देना संभव नहीं है। केवल सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे।

1 टयूबवेल कनेक्शन पर सरकार की ओर से 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश में 6 लाख टयूबवेल विधिवत चल रहे हैं और सरकार किसानों को लगभग 6 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी सरकार दे रही है।

राज्य गतिशील भू–जल संसाधन क्षमता रिपोर्ट जारी करना

(दिनांक 20.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय भूजल बोर्ड, उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ़, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा की भू–जल प्रकोष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से 31 मार्च, 2022 तक तैयार की गई हरियाणा की गतिशील भू–जल संसाधन क्षमता रिपोर्ट भी जारी की।

इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिन्दू नववर्ष विक्रम संवत 2080 के अवसर पर प्रदेश के लोगों को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही चौत्र नवरात्रों की भी बधाई देते हुए कहा कि नववर्ष प्रदेश के लोगों में सुख समृद्धि लेकर आए व प्रदेश में शांति एवं भाईचारा बना रहे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर भी प्रदेश के लोगों को संदेश देते हुए जल संरक्षण की

महत्वत्ता एवं इसके उपयोग की उचित व्यवस्था अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने जल संरक्षण में लगे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग व अन्य हितधारकों को भी बधाई देते हुए कहा कि जल संरक्षण आने वाले समय की आवश्यकता है तथा हर स्तर पर जल का समुचित उपयोग करने पर अभी से बल देना होगा तभी हम भावी पीढ़ी के लिए जल बचा सकेंगे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

(दिनांक 23.03.2023)

प्रभाव : शहीदी दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर पुष्प अर्पित कर माँ भारती की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज शहीदी दिवस के अवसर पर नेशनल वॉर मेमोरियल आने का मौका मिला, यह एक प्रेरणा देने वाला क्षण है।

हमारे वीर सैनिकों ने अपनी शहादत देकर स्वतंत्रता दिलाई।

उन्होंने कहा कि इस मेमोरियल में तीनों सेनाओं यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना के लगभग साढ़े 26 हजार सैनिकों की शहादत का वर्णन दिया गया है। इन साढ़े 26 हजार सैनिकों में

से लगभग 2500 से अधिक सैनिक हरियाणा से संबंध रखते हैं, यह एक और प्रेरणादायक बात है। निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं को 10 प्रतिशत की जो भागीदारी है सेनाओं में है, यह उसका प्रमाण है।

माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश वे देशभर की जनता से अपील करते हुए कहा कि नागरिक इस वॉर मेमोरियल में आएं और शहीदों की शहादत से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ अहम बैठक

(दिनांक 24.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रमुख अधिकारीयों के साथ बैठक कर कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए अधिकारी सीएम यानी कॉमन मैन और पीएम यानी प्राइमरी मेंबर ऑफ द सोसायटी का ध्यान रखें और हर कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित और पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित करें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

बैठक के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी 15 अप्रैल तक पूरा करें ताकि किसानों को मई माह तक पूरा मुआवजा वितरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जल्द से जल्द सभी कार्य को पूरा करें।

बैठक के दौरान परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, स्वामित्व, चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा, अमृत सरोवर, मेरी फसल–मेरा ब्योरा, दयालू योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल आदि सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।.

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी योजना को तैयार करते समय सरकार का लक्ष्य

साप्ताहिक सूचना पत्र

पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना होता है। इसलिए अधिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अधिकारियों को आम जनता से ज्यादा से ज्यादा संवाद पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों सहित फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रोजाना कम से कम 2 घंटे सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय जनता से मिलने के लिए निर्धारित करें, ताकि आमजनमानस अपनी समस्याओं को सीधे आप तक पहुंचा सके।

उन्होंने कहा कि इन 2 घंटों में इन अधिकारियों के साथ मुख्यालय से भी कोई वीडियो कांफ्रेंसिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से भी नियमित संवाद किया जाए क्योंकि वे भी समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए कि मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को श्नो मीटिंग डेश् के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश देते हुए कहा कि हर विभाग में निदेशक स्तर

साप्ताहिक सूचना पत्र

तक के अधिकारी अपने–अपने विभागों द्वारा जमीनी स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा करने के लिए जिलों का दौरा करें। इसके अलावा, प्रशासनिक सचिव जो जिला ईंचार्ज भी हैं, वे भी अपने–अपने जिलों का माह में एक बार दौरा अवश्य करें, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित वास्तविक स्थिति का पता लग सके कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र को मिल रहा है या नहीं।

इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का चौथा चरण अगले माह से आरंभ हो जाएगा।

इसके लिए अधिकारी अपने–अपने जिलों में 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को चिह्नित करें और उन्हें अलगे चरण में लगने वाले अंत्योदय मेलों में बुलाएं। इसके अलावा, पहले के चरणों में वित्तीय सहायता प्राप्त कर चुके परिवारों द्वारा शुरू किए गए स्व रोजगार के कार्यों का भी मूल्यांकन करें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्याओं के संबंध में लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारियों विशेष कैंप लगाएं यदि कोई गलत जानकारी अपलोड की गई है तो उसे सही भी कर सके।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑटोमेटेड पेंशन बन रही है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए सर्वे किया जाए ताकि लाभार्थियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सके और यदि किसी लाभार्थी की पेंशन नहीं बनी है तो उसका पता लगाया जा सके।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारीयों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो जाए और इसमें जरा भी लापरवाही न करें। अगर इसमें थोड़ी भी कोताही बरती गई तो कार्यवाही के लिए तैयार रहे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नवनियुक्त सीएमजीजीए के साथ बैठक

(दिनांक 24.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम –जीजीए के 7 वें बैच को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी नए नए इनोवेटिव आइडियाज प्रयोग कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करे ताकि उन्हें भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। सीएमजीजीए से उनके अनुभव बारे जानकारी भी ली और उन्हें तत्परता से काम करने का आदेश भी दिया। इस वर्ष, देश भर से 24 युवा पेशेवरों को शासन में सुधार के लिए राज्य की प्राथमिकताओं पर मुख्यमंत्री कार्यालय और हरियाणा सरकार के साथ काम करने के लिए चुना गया है। पूरे भारत से लगभग 2500 युवाओं ने आवेदन किया जिसमें 25 सीएमजीजीए चुने गए। इनमें 14 पुरुष एवं 11 महिलाएं शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य के शासन के लिए उनका योगदान अमूल्य होगा जो विकास और सुशासन की दृष्टि से हरियाणा को एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को मजबूत करेगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का हवाई सर्वेक्षण

(दिनांक 25.03.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का हवाई सर्वेक्षण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा व उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की विशेष गिरदावरी करने के आदेश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। सभी उपायुक्तों को 15 अप्रैल तक यह विशेष गिरदावरी के कार्य को पूरा करने के निर्देश हैं, ताकि किसानों को मई माह तक मुआवजा वितरित किया जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 1300 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को ई–फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने नुकसान का ब्यौरा भरना अनिवार्य है। इसके अलावा, जो किसान स्वयं क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का आकलन नहीं भर सकते वे कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भरवा सकते हैं। सरकार द्वारा उसका खर्च वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसल का बीमा करवाने वाले किसानों को कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है और बीमा न करने वाले किसानों को सरकार द्वारा 15000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

FPO के किसानों से सीधा संवाद करना

(दिनांक 25.03.2023)

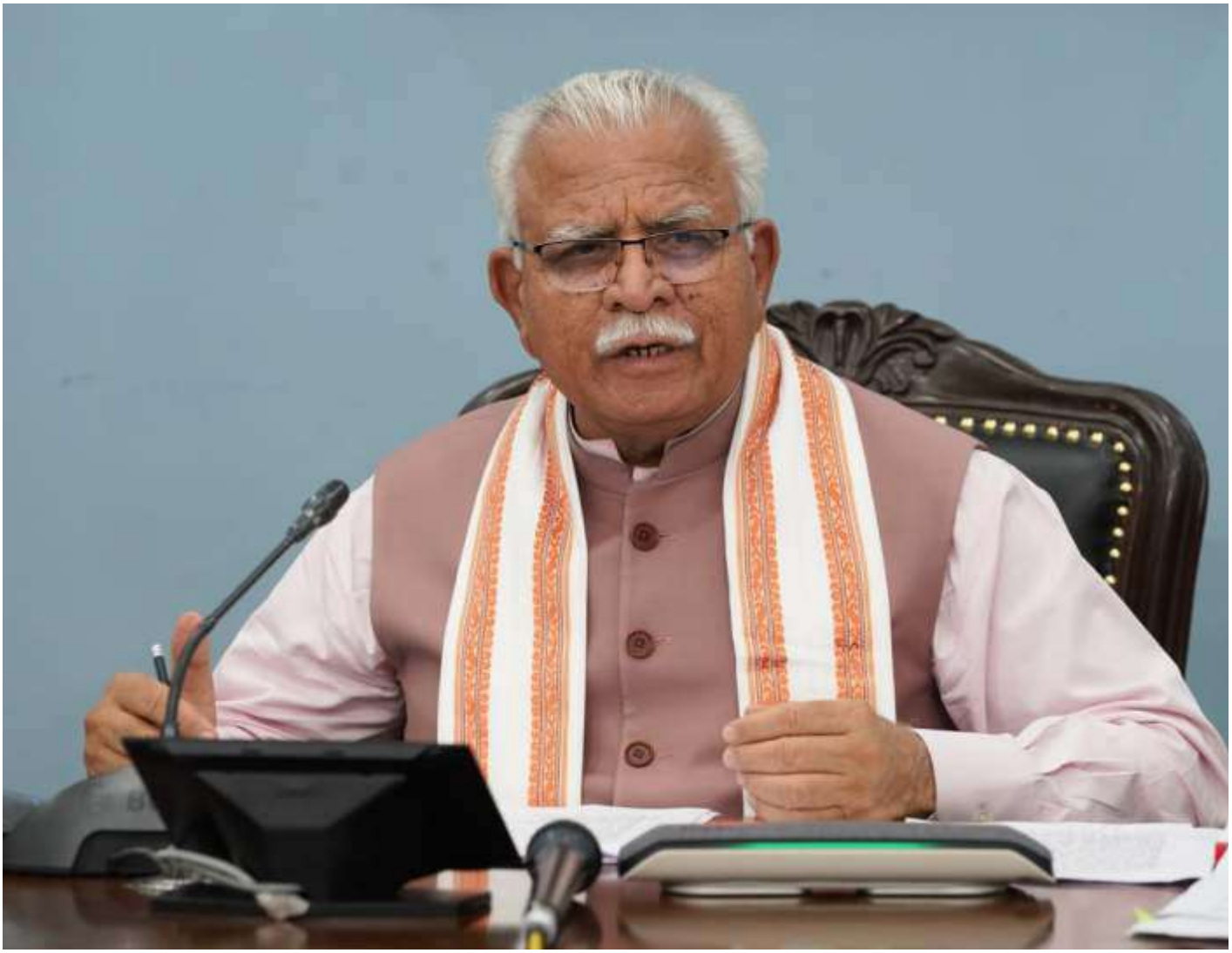

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान उत्पादक समूहों (एफपीओ) के किसानों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद करते हुए किसानों का आह्वान किया कि किसान एफपीओ से जुड़ कर खेती करें, ताकि उनकी कृषि लागत में कमी आए और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके

अलावा, किसान सूक्ष्म सिंचाई, टपका सिंचाई इत्यादि प्रणाली को अपनाएं। उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुसार आज किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आती है और उत्पादन भी बढ़ता है।

किसानों को आधुनिक तकनीक प्रबंधन, भण्डारण, विपणन का ज्ञान प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फरवरी, 2020 में किसान उत्पादक समूह की परिकल्पना की थी। देश में 10 हजार एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। हरियाणा के किसान भी इस योजना का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश में 731 एफपीओ बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज इन एफपीओ की उपलब्धि से प्रेरणा प्राप्त कर अन्य किसान भी एफपीओ से जुड़ेंगे। इस दौरान किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए हितकारी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। सरकार की ओर से एफपीओ को वित्तीय सहायता तथा उत्पादों की ग्रेडिंग, ब्रांडिंग से संबंधित अन्य कई प्रकार की सहायता होने पर किसानों पर आर्थिक बोझ तो कम हुआ ही और साथ ही उन्हें अपनी उपज का सही दाम भी मिलने लगा है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान अपने एफपीओ के माध्यम से पैक हाउस बनाकर उसमें अपनी उपज का भंडारण कर उसे खराब होने से बचा सकते हैं। साथ ही उपज की ग्रेडिंग और पैकेजिंग भी स्वयं करके न केवल बिचौलियों के शोषण से बचेंगे, बल्कि बाजार से भी सीधे जुड़ेंगे। साथ ही फसल सीजन समाप्त होने पर भी कृषि उत्पाद की आपूर्ति पैक हाउस से की जाती रहेगी और किसान को आय प्राप्त होती रहेगी। इससे भी आगे बढ़कर किसान विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद स्वयं तैयार कर सकते हैं।